

Name of the Newspaper	दिन्दुस्तान
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	11

## बिजलीकर्मियों के ऊर्जा निगमों का 32,429 कनेक्शन पर करोड़ नुकसान में 97% हिस्सा मीटर लगे: कैग

लखनऊ। सीएजी ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पहले और बाद में बिजली कंपनियों के प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बिजली कंपनियों को बिना मीटर वाले कनेक्शनों जिसमें विभागीय कार्मिक भी शामिल हैं, के कनेक्शन पर मीटर लगाना सुनिश्चित करें। वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए वितरण हानियां तय लक्ष्य के मुताबिक कम करने के साथ ही बिलिंग में व्यापक सुधार करना चाहिए।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के 113 सार्वजनिक निगमों में केवल 39 निगम ही 2,169.50 करोड़ लाभ अर्जित कर सके हैं।

इनमें कुल लाभ में से 89.14 प्रतिशत का योगदान केवल छह निगमों ने हासिल किया है जबकि 27 निगमों को कुल नुकसान 32,429.90 करोड़ रुपये का हुआ है। इस नुकसान में 97.54 प्रतिशत की हिस्सेदारी केवल पांच ऊर्जा क्षेत्र के निगम हैं। सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा में पेश की गई।

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	03

### बिजलीकर्मियों के घर मीटर लगाने का सुझाव

लखनऊ। सीएजी ने सभी विद्युत वितरण निगमों को बिजली कर्मियों के घर में मीटर लगाने का सुझाव दिया है। उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेंस योजना (उदय) की रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए कहा कि कार्मिक के यहां मीटर लगने से सुधार होगा। वितरण हानियां कम होंगी। वहीं रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उदय योजना में प्रदेश सरकार को 30 सितंबर 2015 तक के टर्न राउंड में 2112.66 करोड़ अधिक ऋण लेना पड़ा।

Name of the Newspaper	नवभारत टाइम्स
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	13

## 2.34 लाख बिजली उपभोक्ता बिना मीटर

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : दोनों सदनो में पेश रिपोर्ट में CAG ने पाया है कि यूपी अब भी 12.34 लाख बिजली उपभोक्ता बिना मीटर के हैं। CAG ने पाया कि 2015-16 में यह संख्या 70.60 लाख थी। 2018 तक यह संख्या शून्य करनी थी, लेकिन बिजली कंपनियां कामयाब नहीं हो पाई हैं। CAG ने यह



AI Image

जरूर पाया है कि कंपनियां दोषपूर्ण मीटरों में कमी लाने में कामयाब रही हैं। रिपोर्ट में साफ कहा है कि

बिजली कंपनियां जिस उद्देश्य के लिए गठित की गई थीं, उसमें वह सफल नहीं रही हैं। न तो उनकी वित्तीय स्थिति दुरुस्त है और न ही काम ठीक से कर पा रही हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं से वसूली के प्रयास को भी नाकामी बताते हुए बिजलीकर्मियों से भी तय टैरिफ से वसूली का सुझाव दिया गया है।